

बिहार विधान सभा वादवृत्त ।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान सभा का कार्य विवरण ।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा सदन में शुक्रवार, तिथि १९ फरवरी, १९५४ को ८-१५ बजे पूर्वाह्न में माननीय अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्मा के सभापतित्व में हुआ ।

विधान कार्य : सरकारी विधेयक :

LEGISLATIVE BUSINESS : OFFICIAL BILL :

बिहार लोकल सेल्फ-गवर्नमेंट (अमेंडिंग ऐंड वैलिडेटिंग) बिल, १९५४ (१९५४ की वि० सं० ४) — (क्रमशः) ।

THE BIHAR LOCAL SELF-GOVERNMENT (AMENDING AND VALIDATING) BILL, 1954 (BILL NO. 4 OF 1954).—(contd.)

*श्री इगनेस कुजूर—अध्यक्ष महोदय, कल मैं कह रहा था कि हमारी सरकार यह जो

शिक्षा प्रसार नीति ले रही है वह हमारे राज्य में ऐसा कदम है जो हमारे राज्य को पीछे की ओर ले जा रहा है। सरकार को यह कहना कि इस नीति से आगे की ओर बढ़ेंगे बिल्कुल गलत है। डिस्ट्रिक्ट सुपरिण्डेंट तथा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को शिक्षा प्रसार का जो अधिकार सरकार दे रही है वे इन्कार कैसे कर सकते हैं क्योंकि वे तो सरकार के ही अधीन हैं, सरकार ही के इशारे पर चलेंगे और मंत्रियों की ही शिक्षा नीति राज्य में लागू रहेगी।

अध्यक्ष महोदय, कल जो शिक्षा मंत्री कह रहे थे कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का अधिकार छीना जा रहा है, यह सही है। राष्ट्रीय सरकार भी योजना के भूतार्थिक वह काम होना जा रहा है। ठीक है, यह तो होगा लेकिन जो प्रतिनिधि चुनाव से आये हैं उनके वह अधिकार छिन जायगा और साथ-साथ यह भी देखा रहे हैं कि अहिंसे आहिंसे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से लेकर हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकार तथा रोड के अधिकार सभी छीना जा रहा है। आखिर में एक अवस्था आयेगी कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को कुछ भी काम बाकी नहीं रहेगा और यह कहना कि चुनाव से आये हुए लोगों का अधिकार छीन कर दूसरों के हाथ सौंपना और कहना कि जनतंत्र हम कायम करते हैं यह मुझे पचती नहीं है। अगर सरकार कहती कि हम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को उठा देना चाहते हैं और इन कामों को सरकार की तरफ से करेंगे, केन्द्रीयकरण करेंगे और शिक्षा प्रसार की नीति सरकार ही पर रहेगी तब यह बात हो सकती थी। लेकिन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और लोकल बडीज को कायम रखना और उसके बाद भी उनको काम नहीं करने देना हमको यह मालूम ही नहीं पड़ता है और यह कोई वजह नहीं है कि जब उन्हें काम नहीं दिया जाता है तो उसे रखा जाय। सरकार कहती है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से केवल शिक्षा प्रसार का काम लिया जा रहा है, उनका सभी अधिकार छीना नहीं जा रहा है। मुझे तो समझ में नहीं आती है कि सरकार शिक्षा प्रसार के लिए अपना ऑफिसर रखेगी और फिर कहती है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सभी काम नहीं छीना जा रहा है, यह हमें बंकार तरीका मालूम होता है। यह जो काम हो रहा है वह प्लैनिंग कमिशन के विरुद्ध हो रहा है। ताज्जुब यह है कि सरकार कहती है कि हम आगे बढ़ रहे हैं परन्तु इनके जितने कदम उठते हैं वह पीछे की ओर ले जाने वाला है। इसलिए आपको यहां पर कहेंगे कि जो आपने आर्डिनंस जारी किया है और जिसके अनुसार काम चल रहा है

(b) (i) how many acres of lands have been acquired for the said factory since its start in village Kokorana ;

(ii) what is the total area of the village ;

(c) whether it is a fact that no land so far has yet been secured from the tenants by peaceful negotiation or mutual agreement ;

(d) if answer to the above clauses be in the affirmative, what steps do Government propose to take to rehabilitate the displaced persons and to allay their feelings ?

Shri KRISHNA BALLABH SAHAY : (a) It is a fact that paddy fields are being acquired in village Kokorana for the Muri Aluminium Factory, but no lac orchards are involved in this acquisition.

(b) (i) 187.59 acres of land have already been acquired in village Kokorana for the Aluminium Factory since its start.

(ii) The total area of the village is 321.24 acres.

(c) The answer is in the affirmative.

(d) Under the provision of the Land Acquisition Act, Government are not bound to provide lands for rehabilitating persons whose lands are acquired. Compensation in this case was paid at the following rates for the different classes of lands acquired :—

Don I—Rs. 2,000 per acre.

Don II—Rs. 1,600 per acre.

Don III—Rs. 1,200 per acre.

Don Tanr I—Rs. 800 per acre.

Don Tanr II—Rs. 400 per acre.

Don Tanr III—Rs. 250 per acre along the road side.

Waste—Rs. 100 per acre along all the other lands.

The persons concerned can rehabilitate themselves from the money received by them as compensation.

RECENT SURVEY OPERATION IN THE STATE.

***379. Shri CHANDRA SHEKHAR SINGH :** Will the Revenue Minister, be pleased to state—

(a) the results obtained by Government due to the recent survey operations in the State ;

(b) whether Government contemplate to extend the survey operations to other parts of the State, if so, to what areas are they likely to be extended in the near future ?

Shri KRISHNA BALLABH SAHAY : (a) The survey and settlement operations in the district of Purnea are going on at present in Forbesganj, Araria, Raniganj, Bahadurganj, Dhamdaha, Korha and Safiganj thanas, covering a total area of 2,650 sq. miles. The total area of the district being 4,994 sq. miles, the survey and settlement operations will cover a little over half the district during the current year. Out of this, 2/3rd of the area is under Kistwar and Khanapuri and 1/3rd of the area is under Attestation. It is thus too early yet to say the final result from the survey and settlement operations.

(b) The final closing of the survey and settlement operations in the Purnea District will take about two years more. The question of extending the operations to other districts will be considered after the Purnea district operations are well in the way to completion.

Shri CHANDRA SHEKHAR SINGH : Are Government aware of the defects that are being realised in the new survey and settlement operations?

Shri KRISHNA BALLABH SAHAY : Undoubtedly.

Shri CHANDRA SHEKHAR SINGH : What are those defects that were brought to the notice of the Government?

Shri KRISHNA BALLABH SAHAY : For that I shall require a fresh notice.

Shri CHANDRA SHEKHAR SINGH : What steps, if any, have been taken by Government to remove those defects?

Shri KRISHNA BALLABH SAHAY : I find from the reports of the non-officials and officials that there are some defects but those defects will be removed when survey operations in other districts will be carried on. But I may say that there is much satisfaction over the operations that are going on in the district of Purnea.

Shri CHANDRA SHEKHAR SINGH : Will Government be pleased to state what are the basis for selecting a certain area for carrying out survey operations?

Shri KRISHNA BALLABH SAHAY : We consulted both non-officials and officials and also some important public men and we found that public opinion was in favour of survey and settlement operations and therefore, Purnea district was selected for the purpose.

Shri CHANDRA SHEKHAR SINGH : I would like to know what were the particular points on which non-officials opinion was gathered?

Shri KRISHNA BALLABH SAHAY : There was no particular point. We were simply concerned with survey and settlement operations and on this point alone non-officials opinion was obtained and it was in favour of the operation.

Shri CHANDRA SHEKHAR SINGH : I only wanted to know why Purnea was chosen for the purpose ?

Shri KRISHNA BALLABH SAHAY : It was selected for administrative reasons. Revenue system such as Patni and Dar Patni is more complicated there.

Shri CHANDRA SHEKHAR SINGH : What basis will form for selecting areas for survey operations elsewhere ?

Shri KRISHNA BALLABH SAHAY : Since survey and settlement operations are succeeding in Purnea district we want to extend it to other districts.

Shri BINDESHWARI PRASAD MANDAL : Whether it is possible to extend survey and settlement operations at one and the same time in the whole of the State ?

Shri KRISHNA BALLABH SAHAY : It is not possible to extend as it is being done because we shall require a number of officers who can take up this work. We shall have to take into consideration the record of rights, etc., and unless such things are available we cannot take up survey operations in all the districts.

श्री कर्पूरी ठाकुर—जब द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस सिद्धान्त को मान लिया

गया है कि "प्लानिंग फ्रीम बिलो" तो हम जानना चाहते हैं कि सरकार क्या आवश्यक नहीं समझती कि उस काम को सही रूप से चलाने के लिए सर्वे सेटलमेंट ऑपरेशन शीघ्र सारे सूबे में शुरू किया जाय ?

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—जितना विश्वास सर्वे सेटलमेंट ऑपरेशन में हमारे दोस्त

कर्पूरी ठाकुर को है उतना हमें भी है। लेकिन इस काम को बड़े पैमाने पर करने के लिए हमारे पास मजिनरी तत्काल मौजूद नहीं है। फिर भी हम इस काम को कर सकते हैं अगर पोलिटिकल पार्टों हमारे साथ इस काम में सहयोग करे। लेकिन हम देखते हैं कि जो पोलिटिकल पार्टों हैं वह इससे लाभ उठाती हैं।

श्री कर्पूरी ठाकुर—क्या सरकार बतायेगी कि पूर्णियां जिले में जो सर्वे सेटलमेंट

ऑपरेशन का काम हुआ था उसमें वहां की राजनीतिक पार्टियों ने सरकार के साथ सहयोग किया था ?

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—में इस काम में सोशलिस्ट पार्टों को सर्टिफिकेट देने के लिए तैयार नहीं हूँ।

श्री कर्पूरी ठाकुर—मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार कांग्रेस पार्टी को इसके लिए सर्टिफिकेट देने को तैयार है या नहीं ?

अध्यक्ष—यह तो प्रश्न के बाहर की चीज है।

पं० विनोदानन्द झा—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अभी जो सर्वे सेटलमेंट ऑपरेशन हो रहा है या भविष्य में होगा, क्या वह बंगाल टिनेन्सी ऐक्ट के दफा (१०२) के अन्दर किया जायेगा या इसके अलावे कोई दूसरी कल्पना सरकार करती है ?

अध्यक्ष—माननीय मंत्री ने अभी बताया कि जमींदारियों के उन्मूलन के बाहर वे कोई ऐसी मशिनरी कायम करेंगे जिसके जरिये यह काम वे आसानी से करा सकेंगे।

पं० विनोदानन्द झा—मैं यह जानना चाहता हूँ कि जो सर्वे दफा (१०२) बिहार टिनेन्सी ऐक्ट में है वही होगा या सरकार कोई दूसरी इकनॉमिक सर्वे कराना चाहती है ?

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—जिस वक्त हमारा गांव-गांव में मशिनरी तैयार हो जायगा जैसे अंचल अधिकारियों की जब बहालियां हो जायेंगी और वे अपना काम करना शुरू कर देंगे तब यह काम करने में हमें आसानी होगी।

पं० विनोदानन्द झा—क्या सरकार की यह नीति है कि जिन जिलों में सर्वे बहुत पहले हुए थे और अब वे सेटलमेंट रेकॉर्ड्स आउट ऑफ डेट हो गये हैं वहीं सरकार पहले सर्वे करायेंगी ?

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—सुझाव अच्छा है और इसे में ध्यान में रखूंगा लेकिन यदि किसी जिले में ऐग्रेरियन ट्रबुल होगा तो वहां हम सर्वे पहले करायेंगे।

पं० विनोदानन्द झा—आखिर सरकार तो ऐग्रेरियन ट्रबुल तो नहीं कराती है। इसलिये कहां तक सम्भव होगा कि जहां २ आग लगेंगी वहां वहां पानी के लिए सरकार फिरा करेगी।

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—आपका सुझाव वाजिव है और मैं इसका ख्याल रखूंगा।

श्री राम नारायण मंडल—उत्तर में सरकार ने कहा है कि पूर्णियां के सर्वे का अनुभव के बाद सरकार सोचेगी कि और जिलों में सर्वे कराया जाय या नहीं, मैं जानना चाहता हूँ कि जो अनुभव सरकार को पूर्णियां के सर्वे का प्राप्त हुआ है उस पर सरकार क्या सोचती है कि और जिलों में सर्वे कराया जाय ?

अध्यक्ष—अभी सरकार का अनुभव पूरा नहीं है।

श्री राम नारायण मंडल—सरकार ने कहा है कि जहां एंग्रेरियन ट्रबुल होगा वहां सर्व पहले करायगी तो क्या सरकार बतलायगी कि अभी जो सर्व पूर्णियां जिला में हो रहा है उसके फलस्वरूप एंग्रेरियन ट्रबुल में कमी हुई या प्रगति हुई है?

अध्यक्ष—यह प्रश्न नहीं उठता।

रोसड़ा थाने में भयंकर बाढ़ से फसल की क्षति।

*३८०। श्री कर्पूरी ठाकुर—क्या मंत्री, राजस्व विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे

कि—

(क) क्या यह बात सही है कि रोसड़ा थाने में ३६६ गांवों में से ३६० गांवों में भयंकर बाढ़ आयी थी;

(ख) क्या यह बात सही है कि वहां न तो भदई फसल हुई और न अगहनी और गन्ना भी अत्यन्त कम हुआ;

(ग) क्या यह बात सही है कि उक्त थाना में (चिलीज) मिरचाई के पौधों में फल ही नहीं लगा है और इस कारण नकद फसल (कैश क्रौप) से भी कोई आमदनी नहीं हुई है;

(घ) क्या यह बात सही है कि थाने भर में अभी पैसा और अन्न नहीं रहने के कारण मजदूर, किसान और मध्यम श्रेणी के लोगों में हाहाकार मचा हुआ है और बहुत घरों में फाकाकशी भी चल रही है, यदि हां, तो सरकार वहां की जनता के शीघ्र कष्ट निवारण के लिये क्या करने का विचार करती है?

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—(क) और (ख) यह बात सही है कि रोसड़ा थाना में ३६६

गांव हैं उनमें ३५६ गांव में गत वर्ष बाढ़ आ गई थी। १३, १४, १५ और १६ सर्कल जो कोसी एरिया में है यहां बाढ़ प्रति वर्ष आती है। यह बात सही है कि सर्कल नं० २ से १० में भदई और अगहनी फसल नहीं हुई थी मगर सर्कल नं० १ में भदई फसल अच्छी हुई थी। सर्कल नं० १४ और १५ और सर्कल नं० १२ और १३ के ज्यादा हिस्सों में धान की फसल अच्छी हुई थी। सर्कल ७ से ११ में धान की फसल अच्छी थी। ऊख की फसल को भी बाढ़ से नुकसान पहुंचा था।

(ग) यह सही नहीं है कि मिरचाई की फसल कामयाब नहीं हुई और उससे जो नकद आमदनी होती थी वह नहीं हुई। लेकिन यह सही है कि मिरचाई की फसल गत वर्ष ने नुकसान में अच्छी नहीं हुई थी।

(घ) यह बात सही नहीं है कि रुपया और अन्न के अभाव से यहां के लोग कराह रहे हैं और कुछ लोग भूखों मर रहे हैं। जिनको जमीन है उन्हें ऋण दिया गया है और जिनके पास जमीन नहीं है उनके लिए हार्ड मैनुअल लेबर की योजना चालू की गयी है।

श्री कर्पूरी ठाकुर—मैं व्यक्तिगत रूप से यह जानता हूं कि वहां के लोगों की दशा अच्छी नहीं है, इसलिए क्या सरकार उन लोगों को अधिक रुपया देना चाहती है?